आकाशवाणी

क्षेत्रीय समाचार

देहरादून (उत्तराखण्ड)

शनिवार 02.08.2025

समय 07.20

पहले मुख्य समाचार :–

- पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के तौर पर आज देशभर के नौ दशमलव सात करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे बीस हजार पांच सौ करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
- मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए राज्य सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य किया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डांडा नूरीवाला में 58 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से बनने वाले ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास किया।
- पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का अनंतिम आरक्षण जारी, आचार संहिता हुई समाप्त।

किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें देशभर के नौ दशमलव सात करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे बीस हजार पांच सौ करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इससे इस योजना के तहत कुल वितरण तीन लाख नब्बे हजार करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा।

वहीं, इस किश्त के तहत उत्तराखंड के 8 लाख 28 हजार से अधिक लाभार्थी किसानों को 184 दशमलव 25 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि अब तक 19 किश्तों में राज्य के किसानों को तीन हजार 111 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरादून के हरवंश कपूर मेमोरियल हॉल, गढ़ी कैंट में आयोजित होगा। इसके साथ ही अन्य स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे।

पंजीकरण अनिवार्य

शासन ने अब चारधाम और हेमकुंड साहिब की तर्ज पर मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए भी पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। इस दिशा में पर्यटन विभाग ने एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत कर दी है।

पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस नई व्यवस्था के जरिए अब पर्यटकों की संख्या का सटीक आंकलन किया जा सकेगा। साथ ही, पर्यटन सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा, ताकि आने वाले सैलानियों को किसी तरह की असुविधा न हो।

श्री गर्ब्याल ने यह भी कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी इस तरह की पंजीकरण प्रणाली लागू करने की योजना बनाई जा रही है।

घोषणाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की घोषणाओं और अन्य कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकगणों से निरंतर संवाद बनाए रखें और उनकी प्राथमिकता वाले कार्यों में तेजी लाएं। किसी कार्य में समस्या आने पर संबंधित विधायक, सचिव और विभागाध्यक्ष मिलकर समाधान निकालें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 70 विधानसभाओं में घोषणाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शासन–प्रशासन और विधानसभा क्षेत्र के बीच सेतु की भूमिका निभाने के लिए अपर सचिव स्तर के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। हर विधानसभा में सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत को उजागर करते हुए नवाचार करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने हरिद्वार में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए विस्तृत योजना और सर्वे का काम जल्द पूरा करने को कहा। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर स्थायी जल व्यवस्था के लिए एक माह में डीपीआर तैयार करने और संजय झील को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

राज्य गंगा समिति की बैठक

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य गंगा समिति की 18वीं बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने गंगा संरक्षण और कायाकल्प से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यदायी संस्थाओं को गंभीरता से काम करने को कहा। जिला गंगा समितियों की बैठकें समय पर कराने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्य सचिव ने जल निगम के अंतर्गत सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण शीघ्र पूरा करने और नई प्लांट बनाने से पहले समिति की संस्तुति लेने पर जोर दिया। कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग के एसटीपी निर्माण में हो रही देरी पर संबंधित जिलाधिकारियों को भूमि हस्तांतरण सहित सभी कार्य एक माह में निपटाने को कहा गया।

श्री बर्धन ने पूरे राज्य में सीवेज प्रबंधन का गैप एनालिसिल करने तथा गंगा की सहायक नदियों के बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण और जलविज्ञान सर्वेक्षण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

शिलन्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्रधारा रोड स्थित डांडा नूरीवाला में 58 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से बनने वाले ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होगा, जहां विभाग की प्रमुख योजनाएं एक ही परिसर से संचालित होंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार "एक जनपद, दो उत्पाद" योजना के जरिए स्थानीय आजीविका को बढ़ावा दे रही है और "हाउस ऑफ हिमालयाज" ब्रांड से पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला रही है। श्री धामी ने जोर देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 25 करोड़ रुपये के कारोबार का है, जिससे हजारों युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्थायी आजीविका से जोड़ा जा सके।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह भवन पहाड़ी शैली में बनाया जाएगा और इसमें सौर ऊर्जा की संपूर्ण व्यवस्था होगी।

परिणाम घोषित/आचार संहिता निष्क्रिय

प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी परिणाम घोषित होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण का अनंतिम प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। इस प्रस्ताव पर 2 से 4 अगस्त के बीच आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम आरक्षण 6 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा।

पंचायती राज विभाग ने पहली बार पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार द्वारा जारी आरक्षण प्रस्ताव में कहा गया है कि ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है।

उधर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में लागू आचार संहिता को निष्प्रभावी कर दिया है। इस बार चुनाव दो चरणों में 24 और 28 जुलाई को कराए गए थे, जिनकी मतगणना 31 जुलाई को शुरू हुई थी। शुक्रवार शाम तक सभी जिलों के परिणाम घोषित होने के बाद आचार संहिता हटा दी गई है।

भेंट / चर्चा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारतीय सेना की मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में सेना द्वारा स्थानीय समुदायों की सहायता और प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्यों में दिए गए सहयोग की सराहना की। मुख्यमंत्री ने सेना के योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनकी सभी महत्वपूर्ण पहलों में सहयोग करती रहेगी।

लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता ने सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास के लिये मध्य कमान की ओर से संचालित कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना सुरक्षा के साथ–साथ सामाजिक विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण, युवाओं से संवाद और अग्रिम क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पहल कर रही है।

नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू किए गए "नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान" को प्रदेशभर में व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। इस अभियान के तहत सरकारी और गैर–सरकारी विद्यालयों को जोड़ा जा रहा है, ताकि बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सके।

सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि इस मुहिम को हर जिले और हर विद्यालय तक पहुंचाकर जनांदोलन का रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से स्कूली छात्रों पर केंद्रित जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी नशे से मुक्त, जागरूक और सशक्त बन सके।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष के बीच निर्दलीयों की जीत की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है।

अमर उजाला ने लिखा है– पंचायत चुनाव में निर्दलीयों का डंका, भाजपा आगे और कांग्रेस को भी बढ़त। दैनिक जागरण का शीर्षक है– भाजपा बम–बम, निर्दलियों ने भी दिखया दम।

उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शासन द्वारा अनंतिम आरक्षण जारी करने की खबर को भी सभी समाचारों ने प्राथमिकता दी है। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने शीर्षक दिया है– देहरादून में अध्यक्ष पद पर फिर महिला को मौका। दैनिक जागरण की सुर्खी है– छह जिलों में महिलाओं को कमान।

राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है– देहरादून और टिहरी में महिला होगी जिला पंचायत अध्यक्ष।

उपराष्ट्रपति चुनाव की खबर पर दैनिक जागरण लिखता है– उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नौ सितम्बर को, अधिसूचना जारी। राष्ट्रीय सहारा लिखता है– कड़े मुकाबले के आसार, सात अगस्त को जारी होगी अधिसूचना।